भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1132

जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026/2 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक सब्सिडी का आवंटन

1132. श्रीमती रुचि वीरा:
श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर:
श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कृषि के मुख्य मौसम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और लखीमपुर खीरी जिलों सहित देश में एनपीके, डीएपी और यूरिया सहित उर्वरकों की कमी और कालाबाजारी के संबंध में गन्ना किसानों से प्राप्त शिकायतों की जानकारी है और यदि हां, तो उत्तर प्रदेश के उक्त जिलों सहित जिला-वार बफर स्टॉक की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार, उक्त जिलों में आवंटित उर्वरकों की कुल मात्रा कितनी है और वास्तविक मांग का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव आदान लागत को कम करने के लिए उर्वरक सब्सिडी का लाभ सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित करने की प्रक्रिया को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय सहकारी समितियों के माध्यम से अतिरिक्त सब्सिडी/प्रशिक्षण/सब्सिडी वाले किट प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त जिलों में इनका उपयोग करने वाले किसानों का प्रतिशत कितना है;

(ड) क्या सरकार का प्रस्ताव उक्त जिलों में उर्वरक वितरण केंद्रों की संख्या बढ़ाने और एक पारदर्शी डिजिटल निगरानी प्रणाली शुरू करने का है और यदि हां, तो जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से भूजल और मृदा स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है?

<u>उत्तर</u>

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): उत्तर प्रदेश राज्य में चालू खरीफ 2026 मौसम के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त है। दिनांक 21.07.2026 की स्थिति के अनुसार राज्य में उक्त उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक के संबंध में विवरण नीचे दिया गया है:

उत्तर प्रदेश					
वर्तमान खरीफ मौसम 2026 (01.04.26 से 21.07.26 तक) के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता					
					आंकड़े एलएमटी में
क्र.सं.	**उत्पाद**	**मांग**	**उपलब्धता**	**डीबीटी बिक्री**	**21.07.26 को अंतिम स्टॉक**
1	यूरिया	23.38	33.66	17.36	16.30
2	डीएपी	4.92	8.63	3.45	5.17
3	एमओपी	1.42	1.37	0.23	1.14
4	एनपीकेएस	1.95	6.26	1.28	4.98

1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता **>** आवश्यकता
2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता **>** बिक्री

हालाँकि, राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) राज्य सरकार के साथ परामर्श करके उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, घटिया उर्वरक पाए जाने और विपथन के मामलों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई की साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से निगरानी कर रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में, अप्रैल 2026 से जुलाई 2026 (17.07.2026 तक) तक, 9,687 छापे मारे गए हैं, चूककर्ताओं के खिलाफ 1,083 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 548 लाइसेंस निलंबित/रद्द किए गए हैं और 38 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी बताया कि राज्य किसानों के हितों की रक्षा करने और उर्वरकों से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जिसमें कालाबाजारी, अतिमूल्य निर्धारण, टैगिंग और अन्य अनियमितताओं को निरंतर निगरानी और प्रवर्तन उपायों के माध्यम से संबोधित करना शामिल है। यूरिया, डीएपी और एनपीके कॉम्प्लेक्स की पर्याप्त मात्रा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध है, जिसमें मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और लखीमपुर खीरी शामिल हैं।

इसका विवरण निम्नानुसार है:-

					मात्रा एमटी में
2024-25				**2025-26**	
क्र.सं.	**जिला**	**आवंटन**	**बिक्री**	**आवंटन**	**बिक्री**
1	मुरादाबाद	1,94,365	1,61,300	1,82,979	1,61,596
2	मुजफ्फरनगर	1,56,282	1,45,552	1,59,448	1,48,110
3	बिजनौर	2,10,764	1,82,471	2,04,352	1,77,082
4	लखीमपुर खीरी	3,22,001	3,36,385	3,47,270	3,39,878

(ग): उर्वरकों में डीबीटी प्रणाली के तहत, प्रत्येक खुदरा दुकान पर स्थापित पीओएस उपकरणों के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के आधार पर लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री पर उर्वरक कंपनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100% सब्सिडी जारी की जाती है।

आज की स्थिति के अनुसार, चूंकि पहचाने गए किसानों का डेटाबेस संतृप्त नहीं है, इसलिए अभी तक प्रत्यक्ष नकद अंतरण की परिकल्पना नहीं की गई है।

(घ): देश भर के किसानों के बीच नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. नैनो यूरिया के उपयोग को जागरूकता शिविरों, वेबिनार, फील्ड प्रदर्शन, किसान सम्मेलनों और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।

ii. नैनो यूरिया और नैनो डीएपी संबंधित कंपनियों द्वारा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

iii. नैनो यूरिया जैसे नैनो उर्वरकों के अनुप्रयोग और उपयोग में आसानी हेतु इनके पर्णीय अनुप्रयोग के लिए, 'किसान ड्रोन' जैसे अभिनव छिड़काव विकल्पों और खुदरा बिंदुओं पर बैटरी चालित स्प्रेयरों के वितरण जैसी पहल की जाती हैं। इस उद्देश्य के लिए, ग्राम स्तरीय उद्यमियों के माध्यम से पायलट प्रशिक्षण और किराए पर छिड़काव (कस्टम हायरिंग स्प्रेइंग) सेवाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाता है।

iv. उर्वरक कंपनियों ने प्रमुख कृषि राज्यों में नैनो उर्वरकों को अपनाने के लिए व्यापक जागरूकता और प्रचार गतिविधियां शुरू की हैं। इनमें किसानों की बैठकें, फसल सेमिनार, फील्ड प्रदर्शन, फील्ड दिवस और उत्पाद उपयोग, पोषकतत्व की दक्षता, लागत लाभ और फसल प्रदर्शन पर किसानों को शिक्षित करने के लिए संस्थागत परीक्षण शामिल हैं।

v. उर्वरक कंपनियों ने नैनो उर्वरकों के सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रसार कार्यकर्ताओं, खुदरा विक्रेताओं और अन्य हितधारकों के लिए अनुसंधान, फील्ड परीक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और राज्य कृषि विभागों के साथ भी भागीदारी की है।

vi. जागरूकता को और बढ़ाने के लिए, कंपनियों ने टेलीविजन अभियान, किसान मेलों, कृषि प्रदर्शनियों, भित्ति चित्रों, होर्डिंग, डीलर प्रदर्शन, मोबाइल अभियान, मुद्रित साहित्य और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब और फेसबुक का उपयोग किया है। किसान गोष्ठियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा गतिविधियों और ग्राम-स्तरीय अभियानों सहित विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

vii. इफको और कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड (सीआईएल) जैसे उत्पादकों ने सूचित किया है कि बातचीत और प्रशंसापत्रों के माध्यम से किसानों की प्रतिक्रिया एकत्र की गई है। कंपनियों के अनुसार, किसानों ने आम तौर पर नैनो उर्वरकों के साथ सकारात्मक अनुभव की सूचना दी है और उनका उपयोग जारी रखने की इच्छा दिखाई है।

प्रोत्साहन के संबंध में, गुजरात और राजस्थान राज्य नैनो यूरिया और नैनो डीएपी पर 50% सब्सिडी प्रदान करते हैं, जबकि उत्तराखंड ने केंद्रीय और राज्य स्कीमों के तहत प्रदर्शनों में उनके उपयोग को अनिवार्य बना दिया है।

(ङ): आईएफएमएस उर्वरक आवंटन, प्रेषण और आपूर्ति स्थिति की ऑनलाइन निगरानी के माध्यम से संचलन नियंत्रण आदेश के कार्यान्वयन और निगरानी के साथ एकीकृत है। उर्वरक विभाग द्वारा अनुमोदित

राज्य-वार और माह-वार आपूर्ति योजनाओं को आईएफएमएस में अपलोड किया जाता है और उर्वरक कंपनियों को तदनुसार प्रेषण करना आवश्यक है। यह प्रणाली कंपनी के एसएपी/ईआरपी सिस्टम के साथ एकीकरण के माध्यम से संचलन और प्रेषण विवरण का संग्रहण करती है और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और लखीमपुर खीरी जिलों सहित अखिल भारतीय स्तर पर उर्वरक की उपलब्धता और आपूर्ति की स्थिति की निरंतर निगरानी प्रदान करती है।

(च): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लखीमपुर खीरी सहित 721 जिलों में संतुलित उर्वरक पर एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाया है। यह अभियान किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन, क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों और जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित संतुलित उर्वरक और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा देता है। मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने और पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता में सुधार के लिए किसानों को जैविक खाद, जैव उर्वरक, हरित खाद और अन्य संधारणीय पोषक तत्व प्रबंधन प्रथाओं के साथ रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

इसके अलावा, सरकार मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता स्कीम के माध्यम से उर्वरक के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है। यह स्कीम सभी कृषि जोतों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) प्रदान करने, उत्पादकता और मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 2014-15 से कार्यान्वित की जा रही है।

मिट्टी के नमूनों को मानक प्रक्रियाओं के अनुसार संसाधित किया जाता है और पीएच, विद्युत चालकता, कार्बनिक कार्बन, उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्वों (जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज और बोरॉन) जैसे मापदंडों के लिए विश्लेषण किया जाता है।

राज्य मृदा प्रयोगशालाओं के अलावा, स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत देश में 1020 स्कूल लघु मृदा प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं। देश भर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड सिफारिशों पर 93781 किसान प्रशिक्षण, 6.80 लाख प्रदर्शन, 7425 किसान मेले/अभियान आयोजित किए गए हैं। स्कीम में सूक्ष्म पोषक तत्वों के प्रचार और वितरण के तहत 1351166 हेक्टेयर क्षेत्र भी शामिल है। वर्ष 2014-15 से अब तक उत्तर प्रदेश में 4.09 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार किए गए हैं या वितरित किए गए हैं।

पिछले 03 वर्षों में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में जारी/सृजित किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) निम्नानुसार हैं:

अंकों में

जिला	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27**	**कुल**
लखीमपुर	9000	15000	28800	200	**53000**

****